International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल कूटनीति एवं भारत की विदेश नीति का बदलता स्वरूप

परीक्षित

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, विभाग, अस्थल बोहर, रोहतक

prixitparashar1997@gmail.com

डॉ० बी० प्रकाश

शोध निर्देशक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

सारांश

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल तकनीक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति, संचार, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया है। कूटनीति, जो परंपरागत रूप से राजनयिक वार्ताओं, दूतावासों, सम्मेलनों और औपचारिक संचार पर आधारित थी, अब सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से भी संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में डिजिटल माध्यमों का उपयोग अधिक दृश्यमान, संस्थागत और बहुआयामी हुआ है। विदेश मंत्रालय तथा भारतीय मिशनों ने डिजिटल संचार के माध्यम से भारत की नीतियों, उपलब्धियों और संकट–प्रतिक्रिया को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाया है।

यह शोध–पत्र 2014 से नवंबर 2026 तक भारत की डिजिटल कूटनीति के विकास का अध्ययन करता है। इसमें सार्वजनिक कूटनीति, नेतृत्व–आधारित संचार, डिजिटल इंडिया, आधार एवं यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे, साइबर कूटनीति, तकनीकी शासन, ळ20 की भारतीय अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण के साथ सहयोग और सामरिक स्वायत्तता का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि डिजिटल कूटनीति भारत की विदेश नीति का स्वतंत्र विकल्प नहीं, बल्कि उसका प्रभावशाली पूरक उपकरण है। इसके माध्यम से भारत अपनी छवि, विकास मॉडल और नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करता हैय साथ ही साइबर जोखिम, डेटा–संप्रभुता, गलत सूचना, डिजिटल असमानता और मंच–निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना भी करता है।

प्रमुख शब्द

डिजिटल कूटनीति, भारत की विदेश नीति, नरेंद्र मोदी, सार्वजनिक कूटनीति, सोशल मीडिया, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, साइबर कूटनीति, G20, वैश्विक दक्षिण, सामरिक स्वायत्तता।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रस्तावना

वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति ने राज्यों के बीच संवाद की गति, प्रकृति और पहुँच को बदल दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल नेटवर्क, डिजिटल भुगतान और डेटा–आधारित सेवाओं ने नागरिकों, सरकारों, कंपनियों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को जोड़ने के नए रास्ते बनाए हैं। विदेश नीति अब केवल विदेश मंत्रालयों और राजनयिक प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं रहीय इसके संदेश घरेलू नागरिकों, प्रवासी समुदायों, विदेशी जनमत, निवेशकों और वैश्विक संस्थाओं तक तत्काल पहुँचते हैं। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक और उभरते आर्थिक राष्ट्र के लिए यह परिवर्तन विशेष महत्त्व रखता है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति के सार्वजनिक संप्रेषण में डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग दिखाई देता है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया मंच, विदेश मंत्रालय के डिजिटल चैनल, भारतीय दूतावासों की ऑनलाइन सेवाएँ तथा डिजिटल इंडिया से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ इस बदलाव के प्रमुख आयाम हैं।

अध्ययन की पृष्ठभूमि एवं समस्या का प्रतिपादन

परंपरागत कूटनीति में सूचना का प्रवाह अपेक्षाकृत नियंत्रित और धीमा था। आधिकारिक वक्तव्य, राजनयिक नोट, प्रेस वार्ता और द्विपक्षीय बैठकें विदेश नीति संचार के मुख्य साधन थे। डिजिटल माध्यमों ने इस व्यवस्था को अधिक खुला बनाया है। सरकारें सीधे विदेशी नागरिकों और प्रवासी समुदायों से संवाद कर सकती हैंय संकट के समय यात्रा–सलाह, निकासी सूचना और सहायता के संदेश तत्काल प्रसारित किए जा सकते हैं। इस अध्ययन की केंद्रीय समस्या यह है कि डिजिटल कूटनीति ने मोदी नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को किस सीमा तक बदला है। क्या डिजिटल मंचों ने भारत की वैश्विक छवि और प्रभाव को मजबूत किया है? क्या डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को भारत ने विकास–सहयोग और तकनीकी कूटनीति के साधन में बदला है? क्या साइबर शासन पर भारत की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अध्ययन डिजिटल संचार और वास्तविक कूटनीतिक परिणामों के बीच अंतर करता है।

शोध के उद्देश्य

इस शोध का प्रथम उद्देश्य डिजिटल कूटनीति की अवधारणा, विकास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उसकी भूमिका को स्पष्ट करना है। दूसरा उद्देश्य 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में डिजिटल संचार के संस्थागत और नेतृत्व–आधारित प्रयोग का विश्लेषण करना है। तीसरा उद्देश्य सोशल मीडिया, सार्वजनिक कूटनीति, प्रवासी भारतीय संपर्क, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय विस्तार का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त शोध का उद्देश्य G20 की भारतीय अध्यक्षता और वैश्विक दक्षिण के संदर्भ में भारत की डिजिटल विकास संबंधी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना है। अध्ययन डिजिटल कूटनीति की उपलब्धियों के साथ उसकी सीमाओं जैसे डिजिटल विभाजन, निजता, डेटा–संप्रभुता, दुष्प्रचार, साइबर सुरक्षा और मंचों पर निर्भरता की पहचान करता है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

शोध प्रश्न एवं परिकल्पना

अध्ययन के प्रमुख प्रश्न हैं: मोदी नेतृत्व के बाद भारत की डिजिटल कूटनीति में कौन–से संस्थागत और व्यवहारगत परिवर्तन आए? सोशल मीडिया ने भारत की सार्वजनिक कूटनीति और वैश्विक छवि को किस प्रकार प्रभावित किया? डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास–सहयोग और विदेश नीति का उपकरण कैसे बना? साइबर सुरक्षा तथा वैश्विक तकनीकी शासन में भारत की प्राथमिकताएँ क्या हैं?

कार्यकारी परिकल्पना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल माध्यम भारत की विदेश नीति के अधिक दृश्यमान और नियमित उपकरण बने हैं तथा उन्होंने भारत की विकास–कथा, नेतृत्व–संचार और वैश्विक दक्षिण के साथ सहयोग को बल दिया है। तथापि डिजिटल कूटनीति पारंपरिक कूटनीति का स्थान नहीं लेतीय उसका प्रभाव संस्थागत क्षमता, विश्वसनीय सूचना, तकनीकी सुरक्षा और ठोस नीतिगत परिणामों पर निर्भर करता है।

शोध–पद्धति एवं अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक और वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। प्राथमिक स्रोतों में विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा, प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों के आधिकारिक दस्तावेज शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में अकादमिक लेख, नीति–अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रकाशित विश्लेषणों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन की समय–सीमा 2014 से नवंबर 2026 तक है। शोध का उद्देश्य प्रत्येक सोशल मीडिया पोस्ट या द्विपक्षीय वार्ता का विवरण देना नहीं, बल्कि प्रमुख प्रवृत्तियों और नीतिगत बदलावों का विश्लेषण करना है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के अनुयायी, पोस्ट और सहभागिता के आँकड़े समय के साथ बदलते रहते हैंय इसलिए उन्हें स्थायी सफलता–सूचक के रूप में नहीं लिया गया है।

डिजिटल कूटनीति : अवधारणा एवं सैद्धांतिक आधार

डिजिटल कूटनीति से आशय विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों और ऑनलाइन माध्यमों के योजनाबद्ध उपयोग से है। इसमें सोशल मीडिया संचार, ऑनलाइन जनसंपर्क, डिजिटल वार्ता, ई–कांसुलर सेवाएँ, साइबर सुरक्षा संवाद, तकनीकी मानक–निर्माण, डिजिटल व्यापार और डेटा शासन शामिल हो सकते हैं। इसे ई–डिप्लोमेसी या ट्विप्लोमेसी जैसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता है।

सैद्धांतिक दृष्टि से डिजिटल कूटनीति को सॉफ्ट पावर, सार्वजनिक कूटनीति, नेटवर्क कूटनीति और बहु–हितधारक शासन से जोड़कर समझा जा सकता है। सॉफ्ट पावर आकर्षण और विश्वसनीयता से प्रभाव पैदा करती हैय सार्वजनिक कूटनीति विदेशी समाजों के साथ संवाद करती हैय नेटवर्क कूटनीति अनेक सरकारी और गैर–सरकारी पक्षों को जोड़ती है। तकनीक अपने–आप प्रभाव उत्पन्न नहीं करतीय संदेश की विश्वसनीयता और संस्थागत निरंतरता निर्णायक रहती है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

पारंपरिक कूटनीति से डिजिटल कूटनीति की ओर

पारंपरिक कूटनीति का आधार गोपनीय वार्ता, औपचारिक प्रतिनिधित्व, प्रोटोकॉल और राज्य–से–राज्य संबंध रहा है। डिजिटल कूटनीति ने इस व्यवस्था में पारदर्शिता और प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद का नया आयाम जोड़ा है। विदेश मंत्रालय किसी निर्णय की व्याख्या सीधे नागरिकों तक पहुँचा सकता हैय दूतावास स्थानीय भाषा में सूचना दे सकते हैंय प्रवासी समुदाय संकट में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इसके बावजूद डिजिटल संचार के कारण कूटनीतिक प्रक्रिया सरल नहीं हुई है। सार्वजनिक मंचों पर दिया गया वक्तव्य तुरंत वैश्विक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है और कभी–कभी वार्ता की गुंजाइश कम कर सकता है। गोपनीयता, संदेश की सटीकता और समय–निर्धारण का महत्त्व बना रहता है। सफल डिजिटल कूटनीति पारंपरिक राजनयिक कौशल का विकल्प नहीं, बल्कि उसका विस्तार है।

मोदी नेतृत्व और विदेश नीति का सार्वजनिक आयाम

2014 के बाद भारतीय विदेश नीति के सार्वजनिक संप्रेषण में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत भूमिका अधिक प्रमुख दिखाई देती है। विदेश यात्राओं, शिखर सम्मेलनों, प्रवासी भारतीय कार्यक्रमों और द्विपक्षीय मुलाकातों से संबंधित संदेश सोशल मीडिया पर साझा किए जाते रहे हैं। इससे विदेश नीति के विषय घरेलू सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने और विदेशी दर्शकों को भारत के नेतृत्व की प्राथमिकताओं का सीधा संकेत मिला।

इस प्रवृत्ति का सकारात्मक पक्ष यह है कि विदेश नीति की जानकारी व्यापक जनसमूह तक पहुँचती है और सरकार अपनी प्राथमिकताओं को सीधे प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन नेतृत्व–केंद्रित संचार में संस्थागत संदेश और व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रांडिंग के बीच संतुलन आवश्यक है। विदेश नीति दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों, संस्थागत निरंतरता और व्यापक राजनीतिक सहमति पर आधारित होती है।

विदेश मंत्रालय और डिजिटल सार्वजनिक कूटनीति

भारत का विदेश मंत्रालय डिजिटल संचार को सार्वजनिक कूटनीति के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग करता है। मंत्रालय की वेबसाइट, सोशल मीडिया खाते, प्रेस विज्ञप्तियाँ, वीडियो संदेश, ऑनलाइन ब्रीफिंग और भारतीय मिशनों के डिजिटल चैनल विदेश नीति संबंधी सूचना प्रसारित करते हैं। विदेश मंत्रालय की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बाह्य प्रचार एवं सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग ने डिजिटल मीडिया और आधुनिक आउटरीच साधनों के माध्यम से भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करने पर जोर दिया।

इसी क्रम में 24 जुलाई 2024 को विदेश मंत्रालय ने अपना आधिकारिक WhatsApp चैनल शुरू किया। यह कदम दर्शाता है कि मंत्रालय पारंपरिक वेबसाइट और सोशल नेटवर्क से आगे बढ़कर उन मंचों तक पहुँचना चाहता है जिनका उपयोग आम नागरिक नियमित रूप से करते हैं। डिजिटल माध्यमों का मूल्य सही सूचना, बहुभाषिक उपलब्धता, नागरिक सहायता और संकट के दौरान भरोसेमंद संचार में है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सोशल मीडिया और भारत की वैश्विक छवि

सोशल मीडिया भारत को अपनी सांस्कृतिक विविधता, लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक अवसरों, वैज्ञानिक उपलब्धियों और विकास कार्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का मंच देता है। योग, आयुर्वेद, भारतीय सिनेमा, पर्यटन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, डिजिटल भुगतान और प्रवासी भारतीय समुदाय से संबंधित सामग्री भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर सकती है।

हालाँकि वैश्विक छवि केवल सकारात्मक संदेशों से निर्मित नहीं होती। मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंटरनेट बंदी, डेटा संरक्षण और सामाजिक तनाव से संबंधित घटनाएँ भी डिजिटल माध्यमों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करती हैं। इस कारण डिजिटल कूटनीति में विश्वसनीयता केंद्रीय तत्व है। सरकारी संचार को आलोचनात्मक प्रश्नों का तथ्यपरक उत्तर देना चाहिए।

प्रवासी भारतीय और डिजिटल संपर्क

प्रवासी भारतीय भारत की सार्वजनिक कूटनीति और आर्थिक संबंधों के महत्त्वपूर्ण सहभागी हैं। डिजिटल मंचों ने प्रवासी समुदायों को भारतीय मिशनों, सरकारी योजनाओं और संकट–सहायता प्रणालियों से जोड़ना आसान बनाया है। ऑनलाइन पंजीकरण, हेल्पलाइन, सोशल मीडिया अपडेट और वर्चुअल संवाद के माध्यम से दूतावास समुदाय की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं।

प्रवासी संपर्क को केवल सांस्कृतिक या राजनीतिक समर्थन के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह व्यापार, निवेश, ज्ञान–विनिमय, शिक्षा, अनुसंधान और स्थानीय समाजों के साथ पुल बनाने का अवसर है। डिजिटल संपर्क का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब भारतीय मिशन स्थानीय भाषाओं और समय–क्षेत्रों के अनुसार सेवाएँ दें और शिकायतों का समयबद्ध समाधान करें।

संकट कूटनीति और डिजिटल सहायता

आपदा, संघर्ष, महामारी या राजनीतिक अस्थिरता के समय डिजिटल संचार जीवनरक्षक भूमिका निभा सकता है। विदेशों में फँसे नागरिकों को सुरक्षित मार्ग, निकासी प्रक्रिया, स्थानीय प्रशासन के निर्देश और दूतावास संपर्क की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन पंजीकरण से सरकार प्रभावित नागरिकों की आवश्यकताओं का आकलन कर सकती है।

फिर भी संकट के समय गलत या अपुष्ट सूचना का जोखिम बहुत अधिक होता है। इसलिए आधिकारिक खातों का सत्यापन, नियमित अपडेट, बहुभाषिक संदेश, स्पष्ट संपर्क विवरण और डेटा सुरक्षा आवश्यक हैं। डिजिटल माध्यम भौतिक निकासी, राजनयिक बातचीत या स्थानीय प्रशासन के सहयोग का विकल्प नहीं हैंय वे इन प्रयासों को समन्वित करते हैं।

डिजिटल इंडिया और विदेश नीति का संबंध

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भारत में डिजिटल अवसंरचना, सेवाओं की उपलब्धता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाना है। घरेलू स्तर पर विकसित पहचान, भुगतान और डेटा–साझाकरण प्रणालियों ने भारत को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

एक विशिष्ट मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। जब भारत इन अनुभवों को अन्य देशों के साथ साझा करता है, तब घरेलू विकास नीति विदेश नीति और विकास–सहयोग से जुड़ जाती है।

डिजिटल इंडिया का विदेश नीति से संबंध तीन स्तरों पर समझा जा सकता हैः तकनीकी साझेदारी, सीमा–पार भुगतान एवं सेवाओं की सुविधा, और डिजिटल मानकों पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, निजता, साइबर सुरक्षा और समावेशिता को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर : भारत का उभरता कूटनीतिक संसाधन

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) ऐसे साझा डिजिटल तंत्रों को कहा जाता है जो पहचान, भुगतान, डेटा विनिमय और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम बनाते हैं। भारत का आधार, यूपीआई और डिजिटल सेवा मंच इस मॉडल के प्रमुख उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। DPI केवल एक ऐप या सरकारी पोर्टल नहीं, बल्कि विभिन्न संस्थाओं और सेवाओं को जोड़ने वाला आधारभूत ढाँचा है।

भारत की DPI कूटनीति का उद्देश्य अपने अनुभवों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करना और तकनीकी क्षमता निर्माण में सहयोग देना है। किंतु किसी देश में भारतीय मॉडल अपनाने से पहले वहाँ की कानूनी व्यवस्था, भाषा, वित्तीय समावेशन, संस्थागत क्षमता और नागरिक अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए।

आधार, डिजिटल पहचान और अंतरराष्ट्रीय विमर्श

आधार ने भारत में डिजिटल पहचान के पैमाने और सार्वजनिक सेवा वितरण पर व्यापक बहस को जन्म दिया है। डिजिटल पहचान के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान, प्रमाणीकरण और विभिन्न सेवाओं तक पहुँच संभव होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का अनुभव उन देशों के लिए उपयोगी अध्ययन–विषय है जो कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं को अधिक कुशल बनाना चाहते हैं।

डिजिटल पहचान का कोई भी मॉडल नागरिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। प्रमाणीकरण विफलता के कारण किसी व्यक्ति को आवश्यक सेवा से वंचित नहीं किया जाना चाहिएय वैकल्पिक पहचान व्यवस्था, शिकायत निवारण और स्वतंत्र निगरानी आवश्यक हैं। भारत को तकनीकी डिजाइन के साथ सुरक्षा परीक्षण, कानूनी संरक्षण और समावेशी सेवा वितरण के अनुभव भी साझा करने चाहिए।

यूपीआई और वित्तीय कूटनीति

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण घटक है। त्वरित भुगतान, बैंक खातों के बीच सरल लेनदेन और अनेक ऐपों के साथ अंतर–संचालनीयता ने इसे घरेलू स्तर पर व्यापक उपयोगिता दी है। UPI का अंतरराष्ट्रीय विस्तार भारत की वित्तीय तकनीक और डिजिटल सेवाओं की क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सरकारी सूचनाओं के अनुसार 2026 में UPI आठ से अधिक देशों में उपलब्ध था, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर शामिल बताए गए। ऐसे विस्तार को नियामकीय सहयोग, भुगतान नेटवर्क के परस्पर जुड़ाव और वित्तीय कूटनीति के रूप में समझना चाहिए।

G20 अध्यक्षता और डिजिटल एजेंडा

2023 में भारत की G20 अध्यक्षता ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को वैश्विक विकास विमर्श के केंद्र में लाने का अवसर दिया। नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में सुरक्षित, विश्वसनीय, जवाबदेह और समावेशी DPI की भूमिका को स्वीकार किया गया। घोषणा ने डिजिटल प्रणालियों के विकास और शासन के लिए स्वैच्छिक ढाँचे का स्वागत किया तथा भारत की Global Digital Public Infrastructure Repository (GDPIR) योजना को समर्थन दिया। G20 के माध्यम से भारत ने डिजिटल विभाजन कम करने, डेटा–आधारित विकास, वित्तीय समावेशन और विकासशील देशों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। One Future Alliance का प्रस्ताव निम्न और मध्यम आय वाले देशों में DPI लागू करने के लिए क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग की दिशा में रखा गया।

वैश्विक दक्षिण और डिजिटल विकास सहयोग

भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ विकास अनुभव साझा करने और उनकी प्राथमिकताओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास किया है। DPI इस प्रयास का नया आयाम है। अनेक विकासशील देशों के सामने नागरिक पहचान, वित्तीय समावेशन, सरकारी सेवाओं की पहुँच और डिजिटल भुगतान की चुनौतियाँ हैं। भारत अपने अनुभवों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी साझेदारियों के माध्यम से सहयोग कर सकता है। वैश्विक दक्षिण के साथ डिजिटल सहयोग बराबरी और स्थानीय स्वामित्व पर आधारित होना चाहिए। भारत को समाधान प्रदाता के साथ–साथ साझेदार देशों से सीखने वाला सहयोगी भी होना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की भागीदारी से परियोजनाएँ अधिक टिकाऊ बन सकती हैं।

साइबर कूटनीति : राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

साइबर क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्त्वपूर्ण आयाम है। सरकारी नेटवर्क, वित्तीय प्रणालियाँ, ऊर्जा अवसंरचना, संचार नेटवर्क और नागरिक डेटा साइबर हमलों के संभावित लक्ष्य हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विभाग का विषय नहीं, बल्कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी है। भारत ने द्विपक्षीय साइबर संवादों तथा संयुक्त राष्ट्र, BRICS और SCO जैसे मंचों पर भागीदारी की है। विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति से संबंधित विशेष संस्थागत व्यवस्था भारत की प्राथमिकता को दर्शाती है। साइबर संवादों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर अपराध से निपटने, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा और वैश्विक नियमों पर विचार–विमर्श शामिल हैं। भारत को सुरक्षा आवश्यकताओं और खुले, स्थिर तथा परस्पर जुड़े इंटरनेट के लाभों के बीच संतुलन बनाना होता है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

NEST प्रभाग और प्रौद्योगिकी कूटनीति

विदेश मंत्रालय का New, Emerging and Strategic Technologies (NEST) प्रभाग 2020 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के विदेश नीति तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहलुओं पर समन्वय करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G और 6G, सेमीकंडक्टर, जैव–प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और क्च् जैसे विषय अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा भू–राजनीतिक शक्ति से जुड़े हैं। NEST प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों, भारतीय मिशनों, उद्योग और विदेशी साझेदारों के बीच संपर्क का कार्य करता है। इसका महत्त्व इस बात में है कि तकनीकी निर्णयों के अंतरराष्ट्रीय प्रभावों को विदेश नीति के दृष्टिकोण से समझा जाए। भारत के लिए चुनौती है कि नवाचार को बढ़ावा देते हुए तकनीकी निर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम और डेटा सुरक्षा से निपटे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक तकनीकी शासन

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, रक्षा और सार्वजनिक प्रशासन को बदल रही है। इसके साथ एल्गोरिदिमक पक्षपात, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, रोजगार, दुष्प्रचार और सुरक्षा से जुड़े प्रश्न भी उत्पन्न हुए हैं। भारत की AI कूटनीति का उद्देश्य नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करना, विकासशील देशों की आवश्यकताओं को सामने रखना तथा सुरक्षित और विश्वसनीय AI शासन के वैश्विक नियमों में योगदान देना है। विदेश मंत्रालय की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) की नई दिल्ली घोषणा सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में भारत की भागीदारी का उल्लेख है। भारत का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो सकता है कि ।प् के लाभ केवल तकनीकी रूप से उन्नत देशों तक सीमित न रहें।

डेटा शासन, निजता और डिजिटल संप्रभुता

डिजिटल कूटनीति के केंद्र में डेटा का नियंत्रण, प्रवाह और संरक्षण है। डेटा आर्थिक मूल्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सीमा–पार डेटा प्रवाह से व्यापार और नवाचार को गति मिल सकती है, लेकिन विभिन्न देशों के निजता कानूनों, डेटा स्थानीयकरण नीतियों और सुरक्षा आवश्यकताओं में अंतर सहयोग को जटिल बनाता है।

डिजिटल संप्रभुता का अर्थ केवल डेटा को देश की सीमा में रखना नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण तकनीकी प्रणालियों पर नियंत्रण, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला, घरेलू क्षमता, नियामकीय स्वायत्तता और नागरिकों का भरोसा शामिल है। भारत को बहुपक्षीय वार्ताओं में स्पष्ट सिद्धांत प्रस्तुत करने चाहिए और उद्योग, नागरिक समाज तथा विशेषज्ञ समुदाय के साथ परामर्श बढ़ाना चाहिए।

भारत–अमेरिका, क्वाड और तकनीकी साझेदारी

भारत–अमेरिका संबंधों में डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों का महत्त्व बढ़ा है। दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग आर्थिक और सामरिक हितों से जुड़ा है। क्वाड के अंतर्गत भी साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और क्षेत्रीय डिजिटल संपर्क पर सहयोग के अवसर मौजूद हैं।

इन सहयोगों के बावजूद भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। किसी एक शक्ति–गुट पर अत्यधिक निर्भरता से तकनीकी और कूटनीतिक विकल्प सीमित हो सकते हैं। इसलिए भारत विभिन्न साझेदारों के साथ मुद्दा–आधारित सहयोग करता है और राष्ट्रीय हित के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास करता है।

चीन, प्रतिस्पर्धा और डिजिटल भू–राजनीति

डिजिटल तकनीक वैश्विक शक्ति–संतुलन का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गई है। दूरसंचार नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री केबल, उपग्रह और डेटा अवसंरचना पर नियंत्रण रणनीतिक प्रभाव पैदा करता है। भारत और चीन के बीच सीमा तथा सुरक्षा संबंधी तनावों ने विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी जोखिमों पर भारत का ध्यान बढ़ाया है।

भारत को तकनीकी सुरक्षा और खुले वैश्विक व्यापार के बीच संतुलन साधना होगा। जोखिम–आधारित मूल्यांकन, विविध आपूर्तिकर्ता, घरेलू अनुसंधान और पारदर्शी सुरक्षा मानक दीर्घकालिक नीति के आधार होने चाहिए। डिजिटल कूटनीति का उपयोग प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संवाद बनाए रखने और साझेदारों के साथ साझा मानक विकसित करने में किया जा सकता है।

बहुपक्षीय संस्थाएँ और इंटरनेट शासन

इंटरनेट शासन में तकनीकी मानक, डोमेन नाम प्रणाली, साइबर अपराध, डिजिटल व्यापार, मानवाधिकार और सीमा–पार डेटा प्रवाह जैसे विषय शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विभिन्न बहुपक्षीय मंच इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत का हित ऐसे वैश्विक शासन में है जो सभी देशों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करे और डिजिटल संसाधनों पर सीमित शक्तियों का एकाधिकार न बनने दे।

इंटरनेट शासन में सरकारों के साथ निजी क्षेत्र, तकनीकी समुदाय, शिक्षाविदों और नागरिक समाज की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। यदि नीति–निर्माण में विविध हितधारकों की भागीदारी सीमित रहेगी, तो नियमों की वैधता और व्यावहारिक प्रभाव कमजोर हो सकते हैं। भारत को घरेलू परामर्श प्रक्रियाओं को मजबूत करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट प्रस्ताव रखने चाहिए।

उपलब्धियाँ और सकारात्मक प्रभाव

मोदी नेतृत्व के दौरान डिजिटल कूटनीति की प्रमुख उपलब्धियों में विदेश नीति संचार की बढ़ी हुई दृश्यता, मंत्रालय और मिशनों की डिजिटल उपस्थिति, प्रवासी भारतीयों से तेज संपर्क, संकट–सूचना का प्रसार तथा डिजिटल विकास मॉडल का अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतीकरण शामिल हैं। DPI और UPI के अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने भारत की तकनीकी क्षमता को आर्थिक और विकास कूटनीति से जोड़ा है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

साइबर कूटनीति और NEST जैसे संस्थागत ढाँचे यह संकेत देते हैं कि भारत तकनीक को केवल आर्थिक क्षेत्र नहीं, बल्कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मानता है। इन पहलों से भारत को नए साझेदारों के साथ सहयोग, वैश्विक नियम–निर्माण में भागीदारी और विकासशील देशों के साथ क्षमता निर्माण के अवसर मिले हैं।

चुनौतियाँ एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन

डिजिटल कूटनीति की पहली चुनौती गलत सूचना और दुष्प्रचार है। सोशल मीडिया पर अपुष्ट सामग्री तेजी से फैल सकती है और विदेश नीति संबंधी संवेदनशील मुद्दों पर भ्रम पैदा कर सकती है। दूसरी चुनौती साइबर हमले और डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा है। तीसरी चुनौती डिजिटल विभाजन है– ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, गरीब समुदायों और कम डिजिटल साक्षरता वाले समूहों की पहुँच सीमित हो सकती है।

एक अन्य समस्या मंच–निर्भरता है। निजी तकनीकी कंपनियों के एल्गोरिद्म, सामग्री नीतियाँ और व्यावसायिक प्राथमिकताएँ सरकारी संदेशों की पहुँच को प्रभावित कर सकती हैं। ऑनलाइन लोकप्रियता को कूटनीतिक सफलता मानने से नीति का मूल्यांकन सतही हो सकता है। समाधान संस्थागत प्रशिक्षण, पारदर्शिता, साइबर क्षमता, स्वतंत्र निगरानी और बहु–हितधारक सहभागिता में निहित है।

नीति–सुझाव

भारत को डिजिटल कूटनीति के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिए जिसमें विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं, भारतीय मिशनों और निजी क्षेत्र की भूमिकाएँ परिभाषित हों। डिजिटल संदेशों के लिए तथ्य–जाँच, संकट–संचार प्रोटोकॉल और बहुभाषिक सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय मिशनों के अधिकारियों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल मीडिया और डेटा संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

भारत को DPI साझेदारियों में स्थानीय स्वामित्व, खुले मानक, निजता–सुरक्षा और स्वतंत्र मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। न्च और डिजिटल पहचान के विस्तार के साथ नियामकीय सहयोग, उपभोक्ता संरक्षण तथा शिकायत निवारण भी मजबूत होना चाहिए। डिजिटल कूटनीति की सफलता अनुयायियों की संख्या के बजाय विश्वास, समस्या–समाधान और साझेदारी की गुणवत्ता से मापी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का सार्वजनिक और तकनीकी आयाम अधिक प्रमुख हुआ है। डिजिटल कूटनीति ने भारत को अपनी नीतियों, विकास अनुभवों और वैश्विक प्राथमिकताओं को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने का अवसर दिया है। सोशल मीडिया और डिजिटल चैनलों ने संवाद की गति तथा पहुँच बढ़ाई है, DPI और UPI ने घरेलू तकनीकी उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जोड़ा हैय साइबर कूटनीति और NEST ने उभरती तकनीकों को विदेश नीति के संस्थागत विमर्श में स्थान दिया है।

फिर भी यह परिवर्तन पारंपरिक कूटनीति के अंत का संकेत नहीं है। राजनयिक वार्ता, विश्वास–निर्माण, आर्थिक संबंध, सुरक्षा सहयोग और बहुपक्षीय समझौते आज भी विदेश नीति के मूल आधार हैं। डिजिटल माध्यम इन प्रक्रियाओं को सक्षम और व्यापक बनाते हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं ले सकते। दीर्घकालिक सफलता तकनीकी नवाचार को लोकतांत्रिक जवाबदेही, नागरिक अधिकारों, साइबर सुरक्षा और समावेशी विकास से जोड़ने पर निर्भर करेगी।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि मोदी युग में भारत की विदेश नीति अधिक डिजिटल, दृश्य और जन–संपर्क उन्मुख हुई है। डिजिटल कूटनीति ने भारत की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने, प्रवासी समुदाय से संवाद करने, विकास सहयोग के नए साधन प्रस्तुत करने और तकनीकी शासन पर अपनी बात रखने में सहायता की है। G20 की भारतीय अध्यक्षता ने DPI को वैश्विक नीति विमर्श में आगे बढ़ाया और वैश्विक दक्षिण के लिए डिजिटल क्षमता निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित किया।

आने वाले समय में भारत को डिजिटल शक्ति और डिजिटल जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। सुरक्षित प्रणालियाँ, विश्वसनीय सूचना, बहुभाषिक पहुँच, डेटा संरक्षण, खुला इंटरनेट और साझेदार देशों की आवश्यकताओं का सम्मान इस दिशा के प्रमुख आधार होंगे। डिजिटल कूटनीति तभी भारत की विदेश नीति का स्थायी और प्रभावी साधन बनेगी जब तकनीकी दक्षता के साथ नैतिकता, पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी सुनिश्चित हों।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन 2024, अध्याय 27, "बाह्य प्रचार एवं सार्वजनिक कूटनीति", विशेष रूप से डिजिटल उपस्थिति तथा 24 जुलाई 2024 को आधिकारिक व्हाट्सऐप चैनल के शुभारंभ से संबंधित विवरण।
2. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन 2024, "नवीन, उभरती एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकियाँ (NEST) तथा साइबर कूटनीति" से संबंधित अध्याययय इसमें साइबर संवादों, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी (GPAI) तथा तकनीकी सहयोग का विवरण दिया गया है।
3. भारतीय दूतावास, रोम, विदेश मंत्रालय के NEST प्रभाग का परिचय, इसमें वर्ष 2020 में NEST प्रभाग की स्थापना तथा उसके कार्यक्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. G20, नई दिल्ली G20 नेताओं की घोषणा, 9 सितंबर 2023, अनुच्छेद 55–57, इसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार (GDPIR) तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के सुरक्षित विकास से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
5. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, "प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार (GDPIR) के पूर्ण होने तथा वैश्विक

दक्षिण में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक प्रभाव कोष (Social Impact Fund) के निर्माण की घोषणा", 23 नवंबर 2023।

6. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, "भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में सहयोग हेतु 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन एवं समझौते किए हैं", 6 फरवरी 2026।
7. राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग, "भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में सहयोग हेतु 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन एवं समझौते किए हैं", 10 फरवरी 2026।
8. कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, "भारत की साइबर कूटनीति की व्याख्या", मार्च 2025, इसमें भारत की साइबर कूटनीति, संस्थागत विकास तथा वैश्विक साइबर शासन से संबंधित विषयों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
9. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन 2024, भारत के विभिन्न द्विपक्षीय साइबर संवादों तथा अंतरराष्ट्रीय साइबर सहयोग से संबंधित विवरण।
10. भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, "ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा : लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं सतत विकास की दिशा में निर्माण", 12 सितंबर 2026य इसमें डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) में सहयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
11. कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, "भारत की साइबर कूटनीति की व्याख्या", मार्च 2025, https://carnegieendowment.org/research/2025/03/interpreting-indias-cyber-statecraft
12. भारतीय दूतावास, रोम, "विदेश मंत्रालय के छैम्ज् प्रभाग का परिचय", https://www.indianembassyrome.gov.in/page/brief-on-nest-division-mea/
13. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन 2024, नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय, 2025, https://www.mea.gov.in/Images/CPV/140725MEAAnnualReport2024English.pdf
14. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, "बाह्य प्रचार एवं सार्वजनिक कूटनीति", वार्षिक प्रतिवेदन 2024, अध्याय 27, https://www.mea.gov.in/Images/CPV/Introduction-and-Synopsis-English.pdf
15. G20, नई दिल्ली G20 नेताओं की घोषणा, 9 सितंबर 2023, https://www.g20.org/wp-content/uploads/2024/10/G20-2023_India_Declaracao-de-Lideres-pdf
16. राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग, "भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में सहयोग हेतु 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन एवं समझौते किए हैं", 10 फरवरी 2026, https://negd.gov.in/press_release/india-has-signed-mou-agreements-with-23-countries-for-cooperation-on-digital-public-infrastructure-dpi/
17. भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो, "भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में सहयोग हेतु 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन एवं समझौते किए हैं, UPI अब

आठ से अधिक देशों में उपलब्ध है", 6 फरवरी 2026, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage[aspx\PRID]2224505

18. भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो, "प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार (GDPIR) के पूर्ण होने तथा वैश्विक दक्षिण में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक प्रभाव कोष के निर्माण की घोषणा", 23 नवंबर 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage[aspx\PRID]1979113
19. भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, "ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा : लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं सतत विकास की दिशा में निर्माण", 12 सितंबर 2026, https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/brics-new-delhi-declaration-building-for-resilience-innovation-cooperation-and-sustainability-september-12-2026/
20. मैनर, इलान, सार्वजनिक कूटनीति का डिजिटलीकरण, शैम : पालग्रेव मैकमिलन, 2019
21. मेलिसेन, जान (संपादक), नई सार्वजनिक कूटनीति : अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर, बेसिंगस्टोक : पालग्रेव मैकमिलन, 2005
22. नाई, जोसेफ एस. सॉफ्ट पावर : विश्व राजनीति में सफलता के साधन, न्यूयॉर्क : पब्लिक अफेयर्स, 2004
23. सीब, फिलिप, वास्तविक समय की कूटनीति : सोशल मीडिया युग में राजनीति और शक्ति, न्यूयॉर्क : पालग्रेव मैकमिलन, 2012